



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 194]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

गृह मंत्रालय

(सीएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 298(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य की सरकार पर लागू होंगे। भारत गणतन्त्र की सरकार और वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 01 नवम्बर, 2013 को किए गए करार का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है। करार का अनुसमर्थन भारत गणराज्य की सरकार द्वारा 01.01.2014 को और वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य की सरकार द्वारा 10.04.2017 को किया गया।

## **दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य तथा वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य के बीच करार**

भारत-गणराज्य तथा वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई दण्डित अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गए हैं :

### **अनच्छेद 1**

### **परिभाषाएं**

इस करार के प्रयोजन के लिए:

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;

- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा अथवा शेष सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन कारावास के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने का कोई दण्ड या उपाय है;
- (घ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दाण्डिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देशों में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है।
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दण्ड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता है या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

## **अनच्छेद 2**

### **सामान्य सिद्धांत**

1. इस करार के प्रावधानों तथा प्रत्येक देश की विधि के अनुसार दण्डित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में संविदाकार देश एक दूसरे को व्यापक पैमाने पर सहयोग करेंगे।
2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी एक संविदाकार देश के भू-भाग में दण्डित किसी व्यक्ति को उसे दी गई सज़ा अथवा शेष रह रही सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है। इस संबंध में दण्डित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
3. अन्तरण का अनुरोध किसी दण्डित व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक है, अथवा संविदाकार देशों के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, संविदाकार देश को और उक्त संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।
4. दण्डित व्यक्ति के अंतरण के लिए अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश में से कोई भी अनुरोध कर सकता है।

## **अनच्छेद 3**

### **केन्द्रीय प्राधिकारी**

1. इस करार को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकार देश एक केन्द्रीय प्राधिकारी को नामोद्घिष्ट करेगा।
2. संविदाकार देशों के लिए इस करार के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी केन्द्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:
  - भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय।
  - वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य के लिए : लोक सुरक्षा मंत्रालय
3. यदि कोई संविदाकार देश अपना केन्द्रीय प्राधिकारी बदलता है, तो वह दूसरे देश को राजनयिक चैनलों के माध्यम से इसके बारे में अधिसूचित करेगा।

## **अनच्छेद 4**

### **अंतरण की शर्तें**

1. इस करार के अंतर्गत किसी दण्डित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
  - (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक हो;
  - (ख) दण्डित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) निर्णय अंतिम हो;
  - (घ) अंतरणकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है;
  - (ङ) दण्डित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध या सैन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो;

- (च) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दण्डित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम एक वर्ष बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो; आपवादिक मामलों में देश तब भी अंतरण करने के लिए सहमत हो सकते हैं जब दण्डित व्यक्ति की सज़ा एक वर्ष से कम की बची हो;
- (छ) व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दण्ड दिया गया था, वो प्राप्तकर्ता देश में अपराध के रूप में दण्डनीय हैं; अथवा यदि उसके अपने भू-भाग में किए जाते तो दण्डित अपराध होते;
- (ज) प्राप्तकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) अंतरण के संबंध में दण्डित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो अथवा, दण्डित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर संविदाकार देश द्वारा जरूरी समझे जाने पर, संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ञ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

### **अनुच्छेद 5**

#### **अंतरण की प्रक्रिया**

1. संविदाकार देश इस करार के सार की सूचना दण्डित व्यक्तियों को देने का प्रयास करेंगे।
2. यदि दण्डित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस करार के तहत अंतरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है :
  - (क) दण्डित व्यक्ति का नाम एवं राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान और प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, और साथ ही उसके पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति और फिंगरप्रिंट, जो भी संभव हो;
  - (ख) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दण्ड आधारित था;
  - (ग) दण्ड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
  - (घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दण्डित व्यक्ति के खिलाफ दण्ड पारित किया गया है;
  - (ङ.) दण्डित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा उसके पूर्व कृत्यों एवं चरित्र के बारे में अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;
  - (च) सभी मामलों में यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी जिसे प्राप्तकर्ता देश विनिर्दिष्ट करे कि वह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दण्डित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
  - (छ) अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति का अनुरोध; और
  - (ज) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दण्ड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य कारक को शामिल करते हुए, एक विवरण जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दण्ड पहले पूरा हो चुका है।
  - (झ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण से सहमत होने के संबंध में अंतरणकर्ता देश का विवरण।
3. यदि दण्डित व्यक्ति अंतरित किए जाने के लिए प्राप्तकर्ता देश को इच्छा व्यक्त करता है तो प्राप्तकर्ता देश इसकी सूचना अंतरणकर्ता देश को देगा। यदि अंतरणकर्ता देश अंतरण के अनुरोध को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित करने के लिए तैयार हो जाता है तो अंतरणकर्ता देश तुरंत प्राप्तकर्ता देश को लिखित में सूचित करेगा और इस अनुच्छेद के पैरा 2 में निर्दिष्ट सूचना प्रदान करेगा।
4. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ भेजेगा जब तब कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय न कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :
  - (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;

- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्य अथवा चूकें शामिल हैं, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में इस प्रकार से दण्ड पारित किया गया है, मानो वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूकें इसके भू-भाग में घटित हुई होती तो वह अपराध होती।
- (ग) दण्डित व्यक्ति के अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के संहिता उसके अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में दण्ड की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की इच्छा और दण्डित व्यक्ति की सज़ा के बाकी बचे हिस्से को लागू करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा
- (ङ.) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।
5. अंतरणकर्ता देश इस अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में दण्डित व्यक्ति को लिखित में सूचित करेगा।

### **अनुच्छेद 6**

#### **अनुरोध एवं जवाब**

1. अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से प्रार्थित देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उन्हीं माध्यमों से सूचित किए जाएंगे।
2. प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

### **अनुच्छेद 7**

#### **सहमति और इसका सत्यापन**

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।
2. अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित गई शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

### **अनुच्छेद 8**

#### **प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव**

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित होगा, के माध्यम से दण्ड के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अधीन दण्ड का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

### **अनुच्छेद 9**

#### **सज़ा का सतत् प्रवर्तन**

1. प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-अवधारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।
2. तथापि, यदि दण्ड की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा, दण्ड को अपने स्वयं के कानून द्वारा धारित दण्ड अथवा उपाय के अनुरूप बना सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, दण्ड अथवा उपाय यथा संभव, अंतरणकर्ता देश के निर्णय द्वारा दिए गए दण्ड के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरणकर्ता देश में दिए गए दण्ड में वृद्धि नहीं करेगा। सज़ा को अनुकूलित करते समय प्राप्तकर्ता देश कारावास की सज़ा को आर्थिक अनुशासित में परिवर्तित नहीं कर सकेगा।

**अनुच्छेद 10****अंतरणकर्ता देश के लिए सज़ा के समापन का प्रभाव**

1. जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दण्ड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस दण्ड को पूरा करने करने के संबंध में प्रभावी मानी जाएगी।

**अनुच्छेद 11****निर्णय और माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण की समीक्षा**

1. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
2. कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दण्ड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

**अनुच्छेद 12****दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. अंतरणकर्ता देश अपने क्षेत्र में लिए गए किसी भी निर्णय की सूचना तुरंत प्राप्तकर्ता देश को देगा जिसके लिए सजा या उसके भाग के प्रवर्तन को समाप्त करना आवश्यक होगा।
2. जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे निर्णय अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दण्ड का प्रवर्तन समाप्त हो गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

**अनुच्छेद 13****दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:
  - (क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
  - (ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दण्डित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह दण्डित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करेगा ताकि वह स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और यह कि कैदी के भाग निकलने के बारे में प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत अपराध के लिए कैदी पर अभियोग चलाया जा सके।
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद 14****पारगमन**

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दण्डित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्तियों के पारगमन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दण्डित व्यक्ति के पारगमन से इंकार करे:
  - (क) यदि दण्डित व्यक्ति वहीं का राष्ट्रिक हो।
  - (ख) यदि अनुरोध से संविदाकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था या कोई अन्य महत्वपूर्ण हित का अतिलंघन होता है।
2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे पारगमन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

**अनुच्छेद 15****लागत**

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर इस करार को लागू करने में हुए किसी भी व्यय को प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की वसूली दण्डित व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर सकता है।

**अनच्छेद 16****भाषा**

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे या उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद होगा।

**अनच्छेद 17****लागू होने का दायरा**

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

**अनच्छेद 18****विवादों का निपटारा**

- (1) केन्द्रीय प्राधिकरण इस करार की व्याख्या, इसके लिए लागू होने या कार्यान्वयन से पैदा होने वाले किसी भी विवाद को परस्पर सुलझाने का प्रयास करेगा।
- (2) यदि केन्द्रीय प्राधिकरण विवाद को परस्पर सुलझाने में समर्थ नहीं होते हैं तो इसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

**अनच्छेद 19****दण्डित व्यक्तियों को सौंपा जाना**

1. अंतरणकर्ता देश द्वारा दण्डित व्यक्ति को प्राप्तकर्ता देश को सौंपे जाने की तारीख एवं स्थान वह होगा जिसके बारे में अंतरणकर्ता देश एवं प्राप्तकर्ता देश के बीच सहमति होगी। प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश से कैदी को ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा तथा अंतरणकर्ता देश के क्षेत्र से बाहर दण्डित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।
2. दण्डित व्यक्ति को सौंपे जाने का कार्य अंग्रेजी भाषा में लिखित रूप में दो प्रतियों में होगा तथा सभी पाठ समान रूप से प्रमाणित होंगे। प्रत्येक संविदाकार राष्ट्र एक पाठ को रखेगा।

**अनच्छेद 20****संशोधन**

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन करार में उल्लिखित तरीके के अनुसार ही प्रभावी होगा।

**अनच्छेद 21****अंतिम प्रावधान**

1. प्रत्येक संविदाकार राष्ट्र इस करार के लागू होने के लिए अपेक्षित विधिक प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में यथाशीघ्र अन्य पक्षकार को सूचित करेगा। यह करार पिछली अधिसूचना की तारीख के दूसरे माह के प्रथम दिन को लागू होगा।
2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि, इसे किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को इसकी समाप्ति का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। इसकी समाप्ति ऐसे नोटिस की तारीख से छः महीने बाद प्रभावी होगी।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दण्डित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।
4. यह करार अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य करारों जिनके वे पक्षकार हैं, के अंतर्गत संविदाकार देशों के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपने संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में वर्ष 2013 के माह नवंबर की तारीख 1 को हिन्दी, वियतनामी एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो (2) प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य  
की ओर से

वियतनाम सोशलिस्ट गणराज्य  
की ओर से

[फा. सं. वी-17011/1/2013-पी आर ]

डेनियल ई. रिचर्डस, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(CS DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 298(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Socialistic Republic of Viet Nam. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic of India and the Government of the Socialistic Republic of Viet Nam on 1.11.2013 is given below. The Agreement was ratified by the Government of the Republic of India on 1.1.2014 and by the Government of the Socialistic Republic of Viet Nam on 10.4.2017.

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Republic of India and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

**Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “Receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;

- (e) “Transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## **ARTICLE 2**

### **General Principles**

1. The Contracting States shall afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement and each State's law.
2. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
3. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.
4. The transfer of sentenced persons may be requested by either the Transferring State or the Receiving State

## **ARTICLE 3**

### **Central Authorities**

1. For the purpose of implementing this Agreement, each contracting State shall designate a Central Authority.
2. Central Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
  - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
  - For the Socialist Republic of Viet Nam: Ministry of Public Security
3. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

## **ARTICLE 4**

### **Conditions for transfer**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
  - (a) the person is a national of the receiving State;
  - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - (c) the judgment is final;
  - (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required;
  - (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law or Military offence;



- (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment; in exceptional cases, the Contracting States may agree to a transfer even if the sentenced person has less than one year;
- (g) the acts or omissions for which that person was sentenced in the Transferring State are those which are punishable as a crime in the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (h) the transfer of custody of the sentenced person to the Receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the Transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.

### **ARTICLE 5**

#### **Procedure for Transfer**

1. The Contracting States shall endeavour to inform sentenced persons of the substance of this Agreement.
2. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the Sentenced Person, as possible;
  - (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
  - (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
  - (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
  - (f) any other information which the Receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
  - (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
  - (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
  - (i) A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person.
3. If a sentenced person expresses an interest to the Receiving State to be transferred, the Receiving State shall so inform the Transferring State. If the Transferring State is

prepared, in principle, to approve the request for transfer, the Transferring State shall promptly inform the Receiving State in writing, and provide the information referred to in paragraph 2 of this Article.

4. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
  - (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
  - (b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
  - (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
  - (d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
  - (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.
5. The Transferring State shall inform the sentenced person in writing of any action taken by the Transferring State or the Receiving State under provision of this Article.

## **ARTICLE 6**

### **Requests and Replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed pro-forma, if any, and addressed by the Central Authority of the Transferring State directly or through diplomatic channels to the Central Authority of the Receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. The Receiving State shall promptly inform the Transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

## **ARTICLE 7**

### **Consent and its Verification**

1. The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with subparagraph (i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## **ARTICLE 8**

### **Effect of Transfer for the Receiving State**

1. The competent authorities of the Receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

## **ARTICLE 9**

### **Continued Enforcement of Sentence**

1. The Receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State. When adapting the sentence, the competent authority of the Receiving State may not convert an imprisonment punishment to a pecuniary sanction.

## **ARTICLE 10**

### **Effect of Completion of Sentence for the Transferring State**

When the receiving State notifies the Transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the Transferring state.

## **ARTICLE 11**

### **Review of Judgment and Pardon, Amnesty or Commutation**

1. The Transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

## **ARTICLE 12**

### **Termination of Enforcement of Sentence**

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

## **ARTICLE 13**

### **Information on Enforcement of Sentence**

1. The Receiving State shall notify the Transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the Receiving State shall take measures to secure his/her arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/ her liable for committing an offence under the relevant law of the Receiving State.
2. The Receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the Transferring State.

**ARTICLE 14****Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall, in accordance with its laws, cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced person(s) being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit
  - (a) if the sentenced person is one of its own nationals.
  - (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

**ARTICLE 15****Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring State. The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other sources.

**ARTICLE 16****Language**

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

**ARTICLE 17****Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed before or after the entry into force of this Agreement.

**ARTICLE 18****Settlement of Disputes**

- (1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

**ARTICLE 19****Handing Over of Sentenced Persons**

1. The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur on a date and at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving State. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the Transferring State.
2. The handing over of the sentenced person shall be made in writing in duplicate in English language. Each Contracting State shall keep one copy.

**ARTICLE 20****Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

**ARTICLE 21****Final Provisions**

1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
2. The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoner who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.
4. This Agreement shall not affect the rights or obligations of the Contracting States under international treaties or other agreements to which they are a party.

**In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by the Republic of India and the Socialist Republic of Viet Nam, have signed this Agreement.**

**Done at New Delhi on the 1<sup>st</sup> day of November 2013, in two (02) originals each in the Hindi, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.**

**FOR THE REPUBLIC  
OF INDIA**

**FOR THE SOCIALIST  
REPUBLIC OF VIET NAM**

[F. No. V-17011/1/2013-PR]

DANIEL E. RICHARDS, Jt. Secy.